

ब्यूज टुडे

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP), 2022 के लागू होने के तीन वर्ष पूरे हुए

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का उद्देश्य प्रौद्योगिकी-आधारित, एकीकृत, कम लागत वाला, मजबूत, सतत और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम सुनिश्चित करना है, ताकि तीव्र एवं समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

- इस नीति को समग्र लॉजिस्टिक्स कार्य-योजना (Comprehensive Logistics Action Plan: CLAP) के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- भारत का लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 13-14% का योगदान देता है और 2.2 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। साथ ही, 2027 तक इसमें रोजगार के एक करोड़ नए अवसर उत्पन्न होने का अनुमान है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के प्रमुख लक्ष्य

- 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करके वैश्विक मानकों के अनुरूप करना।
 - 2030 तक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रैंकिंग में भारत को शीर्ष 25 देशों में लाना।
- भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक की उपलब्धियां:
- यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) ने 160 करोड़ से अधिक डिजिटल लेन-देन को संभव बनाया है।
 - इसके अलावा लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक ने 101 इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs) के माध्यम से 7.5 करोड़ से अधिक आयात-निर्यात कंटेनरों को ट्रैक किया है, जिससे रीयल-टाइम विज़िबिलिटी उपलब्ध हुई है।
 - लॉजिस्टिक्स ईज़ एक्सेस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इंडेक्स ने विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार करके 38वां स्थान दिलाने में योगदान दिया है।
 - 65,000 से अधिक लॉजिस्टिक्स पेशेवरों को प्रशिक्षित किया गया है और 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में अब लॉजिस्टिक्स से संबंधित पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

लॉजिस्टिक्स में सुधार के लिए सरकार की प्रमुख पहलें:

- केंद्र सरकार पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग करके अवसंरचना विकास को एकीकृत कर रही है। इस दिशा में प्रमुख पहलें निम्नलिखित हैं:
 - 35 रणनीतिक स्थलों पर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स (MMLPs) का विकास किया जा रहा है, ताकि मल्टी-मॉडल परिवहन को बढ़ावा मिले।
 - उद्योग-विशिष्ट फ्रेमवर्क तैयार करने हेतु सेक्टरल पॉलिसी फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक्स (SPEL) की शुरुआत की गई है।
 - ग्रीन लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए परिवहन उत्सर्जन मापन उपकरण (TEMT) जैसे उपायों की मदद ली जा रही है।

गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की वार्षिक रिपोर्ट, 2024 जारी की

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के बारे में

- यह भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत की गई थी।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करती है।
- इसका मुख्य उद्देश्य मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकना है।

भारत में मादक पदार्थों की तस्करी की स्थिति:

- भारत की सुभेद्य अवस्थिति: भारत दुनिया के दो प्रमुख मादक पदार्थ तस्करी क्षेत्रों 'डेथ क्रीसेंट' (अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान) तथा 'डेथ ट्रायंगल' (म्यांमार, थाईलैंड, एवं लाओस) के बीच स्थित है।
 - जहां पंजाब, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी के लिए संवेदनशील हैं, वहीं पूर्वोत्तर के राज्य म्यांमार से अपनी निकटता के कारण प्रभावित हैं।
- तटीय मार्ग: मुंबई, गुजरात, केरल, तमिलनाडु जैसे तटीय मार्गों का इस्तेमाल अब सिंथेटिक ड्रग्स और उनके घटकों की तस्करी के लिए अधिक किया जा रहा है।
- उभरती नई प्रवृत्तियां
 - अब मेथामफेटामाइन, LSD, मेफेड्रोन जैसी सिंथेटिक ड्रग्स की अधिक तस्करी की जा रही है।
 - महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, पूर्वोत्तर के राज्यों आदि के संवेदनशील क्षेत्रों में गुप्त रूप से प्रयोगशालाएं चलाई जा रही है।
 - धन के लेन-देन हेतु क्रिप्टोकॉरेंसी के उपयोग तथा डार्कनेट बाजारों के उद्भव ने मादक पदार्थ तस्करों को अनामता और वैश्विक पहुंच प्रदान की है।
 - चाबहार, ग्वादर, कराची आदि बंदरगाहों के माध्यम से समुद्र के जरिये मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है।
 - भारत-पाकिस्तान सीमा के माध्यम से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए भारत द्वारा की गई पहलें:
 - NDPS एक्ट, 1988 में अवैध तस्करी की रोकथाम,
 - नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन पोर्टल (NCORD),
 - गिरफ्तार किए गए नाकों अपराधियों पर राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस (NIDAAN/ निदान),
 - राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन- MANAS/ मानस,
 - नशा मुक्त भारत अभियान आदि।

मादक पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सुझाए गए कदम

- प्रत्येक राज्य को एक उच्च-स्तरीय रणनीति विकसित करनी चाहिए, जो निम्नलिखित तीन तरीकों के कार्टेल्स को निशाना बनाए:
 - वे कार्टेल्स जो प्रवेश बिंदुओं पर काम करते हैं,
 - वे जो राज्यों में वितरण कर रहे हैं, और
 - वे जो छोटे इलाकों में मादक पदार्थ बेच रहे हैं।
- मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल विदेशी अपराधियों और भगोड़ों को वापस लाने के लिए NCB, CBI, और राज्य पुलिस को शामिल करते हुए एक संयुक्त तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।
- प्रत्येक राज्य को एक विशेष दस्ते का गठन करना चाहिए जो-
 - वित्तीय लेन-देन का पता लगाए,
 - हवाला लिंक को ट्रैक करे,
 - क्रिप्टो लेन-देन की निगरानी करे और
 - उभरती हुई तकनीकों के माध्यम से साइबर जांच करे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के ओज़ोन बुलेटिन में ओज़ोन परत की रिकवरी प्रदर्शित की गई

यह बुलेटिन विश्व ओज़ोन दिवस (16 सितम्बर) और वियना कन्वेंशन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया है। विश्व ओज़ोन दिवस 16 सितम्बर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है।

अनुमान है कि ओज़ोन परत 1980 के स्तर (जब ओज़ोन छिद्र पहली बार दिखाई दिया था) तक निम्नलिखित भागों में रिकवरी कर लेगी:

- अंटार्कटिक के ऊपर 2066 तक,
- आर्कटिक के ऊपर 2045 तक और
- दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए 2040 तक।

ओज़ोन परत के बारे में

- ओज़ोन परत पृथ्वी के धरातल से 15 से 30 किमी ऊपर समताप मंडल में स्थित है। यह हमारी सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से रक्षा करती है।
- ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ (ODS): ODS ऐसे पदार्थ हैं, जो क्लोरीन या ब्रोमीन निर्मुक्त करते हैं, और ओज़ोन अणुओं को नष्ट करते हैं।
 - क्लोरीन निर्मुक्त करने वाले ODS में क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFCs), कार्बन टेट्राक्लोराइड (CTC) और मिथाइल क्लोरोफॉर्म शामिल हैं। वहीं ब्रोमीन निर्मुक्त करने वाले ODS में हैलोन और मिथाइल ब्रोमाइड शामिल हैं।
- समताप मंडल में ओज़ोन का क्षरण उत्तरी गोलार्ध (आर्कटिक) की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध (अंटार्कटिका) में अधिक होता है।

वियना कन्वेंशन 1985 के बारे में

- यह पहला वैश्विक समझौता था, जिसने समताप मंडल में ओज़ोन के क्षरण को एक समस्या के रूप में मान्यता दी थी और ओज़ोन पर अंतराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया था।
- इसने ओज़ोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रोटोकॉल को 1987 में अपनाया गया था।
 - मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत नियंत्रित ODS के उत्पादन और खपत के 99% से अधिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किंगाली संशोधन को 2016 में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए अपनाया गया था। HFCs एक ग्रीनहाउस गैस है, जिसका उपयोग ODS के विकल्प के रूप में किया जाता है।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत भारत की उपलब्धियां:

- समय से पहले ODS का चरणबद्ध समापन: भारत ने 2010 तक नियंत्रित उपयोग के लिए CFCs, CTC और हैलोन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया है।
- नीतिगत फ्रेमवर्क: वर्ष 2000 में ओज़ोन-क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) नियम बनाए गए। इसके तहत 2003 तक नए उपकरणों में CFCs और हैलोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- HCFC का चरणबद्ध समापन: भारत ने HCFC के उत्पादन और खपत में 67.5% की कमी हासिल की है और 2020 तक HCFC-141b को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII), 2025 जारी किया

ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) दुनिया के 139 देशों के नवाचार प्रदर्शन का मापन करता है। ऐसा निवेश पैटर्न, तकनीकी प्रगति, अपनाने की दर और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के आधार पर किया जाता है।

इस सूचकांक की शुरुआत 2007 में की गई थी। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीतियों के लिए एक आधिकारिक संदर्भ के रूप में मान्यता प्राप्त है।

GII 2025 के प्रमुख बिंदुओं पर एक नजर:

- भारत का उदय: 2015 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 81वीं थी, जो वर्तमान में 38वीं हो गई है।
 - भारत वियतनाम के साथ सबसे लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। भारत लगातार 15वें साल अपने विकास स्तर की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
- सबसे नवोन्मेषी अर्थव्यवस्थाएं: सूचकांक में शीर्ष स्थान पर स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर का स्थान है।
- शीर्ष नवाचार क्लस्टर: शेन्जेन-हांगकांग-गुआंगझोउ (चीन और हांगकांग) तथा उसके बाद टोक्यो-योकोहामा (जापान), तथा सैन जोस-सैन फ्रांसिस्को (संयुक्त राज्य अमेरिका) हैं।
 - भारत के चार क्लस्टर शीर्ष 100 में हैं: बेंगलुरु (21वां), दिल्ली (26वां), मुंबई (46वां) और चेन्नई (84वां)।

नवाचार में सुधार के लिए भारत की पहलें

- स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम: यह स्टार्ट-अप को आरंभिक सहायता, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से वित्त-पोषण, क्रेडिट गारंटी, कर छूट आदि प्रदान करता है।
- अटल इनोवेशन मिशन: यह विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम एवं नीतियां तैयार करता है।
- नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस (NIDHI/ निधि): यह सफल स्टार्ट-अप में विचारों को पोषित करने के लिए एक अम्बेला कार्यक्रम है।
- अन्य: एक्सीलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज़ इनोवेशंस (AGNI) मिशन, नीति फ्रंटियर टेक रिपॉजिटरी, प्रधान मंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना, आदि।

भारत का नवाचार परिदृश्य



ज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पादन

- अंतराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग: 22.2% की वृद्धि (2023-2024)।
- वैज्ञानिक प्रकाशन: अल्पकालिक 7.7% और दीर्घकालिक 7.3% की वृद्धि।



क्रेडिट आउटपुट

- 2023 में 49वां; 2024 में 43वां; और 2025 में 42वां स्थान।
- मजबूत सांस्कृतिक और रचनात्मक सेवाओं का निर्यात (वैश्विक स्तर पर 13वें स्थान पर)।



भारत की नवाचार संबंधी बढ़त

- ICT सेवा निर्यात: वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर।
- घरेलू बाजार का पैमाना: वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर।
- वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम: अंतिम चरण की VC डील में चौथे स्थान पर।
- यूनिकॉर्न मूल्यांकन: वैश्विक स्तर पर 11वें स्थान पर।
- इनटेंजिबल एसेट इंटेसिटी: वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर।
- नवाचार दक्षता: उच्च आउटपुट-टू-इनपुट अनुपात।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपडेटेड 24वीं 'आवश्यक औषधियों की मॉडल सूची (EML)' जारी की

WHO की आवश्यक औषधियों की मॉडल सूची प्रत्येक दो वर्षों में 'आवश्यक औषधियों' के चयन और उपयोग पर विशेषज्ञ समिति' द्वारा अपडेट की जाती है।

आवश्यक औषधियों की मॉडल सूची में शामिल नई दवाइयाँ:

- ▶ ग्लूकागन-लाइक पेप्टाइड-1 (GLP-1) रिसेप्टर एगोनिस्ट्स: टाइप-2 डायबिटीज, हृदय रोग, क्रॉनिक किडनी डिजीज और मोटापे के लिए।
- ▶ रैपिड-एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स: टाइप-1 और टाइप-2 डायबिटीज के लिए।

WHO के कदम का महत्व:

- ▶ सूची में शामिल होने के बाद उपर्युक्त महंगी दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी,
 - ▶ इलाज के लिए अपनी जेब से कम खर्च करने पड़ेंगे, और
 - ▶ अधिक लोगों को ये दवाइयाँ उपलब्ध हो पाएंगी।
- डायबिटीज और मोटापे (Obesity) के बारे में
- ▶ डायबिटीज का कारण: डायबिटीज तब होती है, जब अग्न्याशय (Pancreas) पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता, या शरीर बनी हुई इंसुलिन का प्रभावी तरीके से उपयोग नहीं कर पाता।
 - ⊕ विश्व में पीड़ित लोग: 2022 में 800 मिलियन से अधिक लोग डायबिटीज से पीड़ित थे। 2050 तक यह संख्या बढ़कर 1.3 बिलियन से अधिक हो जाने अनुमान का है।
 - ⊕ भारत में पीड़ित लोग: 18 वर्ष से अधिक उम्र के 7.7 करोड़ लोग टाइप-2 डायबिटीज से पीड़ित हैं और लगभग 2.5 करोड़ लोग प्री-डायबिटिक हैं।
 - ▶ मोटापे का कारण: शरीर में अत्यधिक चर्बी जमा होना, जिससे टाइप-2 डायबिटीज, हृदय रोग आदि का खतरा बढ़ जाता है।
 - ⊕ विश्व में मोटापे से पीड़ित लोग: इनकी संख्या 1990 से अब तक दोगुनी हो गई है; वर्तमान में 1 बिलियन से अधिक लोग मोटापे से पीड़ित हैं।
 - ⊕ भारत में मोटापे से पीड़ित लोग: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 (2019-21) के अनुसार 24% भारतीय महिलाएं और 23% भारतीय पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं।

भारत की पहले:

- ▶ गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NP-NCD) शुरू किया गया है।
- ▶ आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLEM): यह स्वास्थ्य-देखभाल सेवा के सभी स्तरों पर किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
- ▶ प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP): इसका उद्देश्य जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत सुनवाई वाले 53 मामलों में 94% से अधिक की दोषसिद्धि दर दर्ज की गई है

ED ने पीड़ितों को 34,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लौटाने में भी मदद की है। उच्च दोषसिद्धि और धन वापसी का महत्व

- ▶ यह PMLA और ED की जांच प्रक्रियाओं के अधिक प्रभावी होने को दर्शाता है।
- ▶ यह दर्शाता है कि ED केवल अपराधियों को दंडित करने में ही नहीं, बल्कि पीड़ितों को क्षतिपूर्ति दिलाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है।

ED के समक्ष चुनौतियाँ

- ▶ उच्च दोषसिद्धि दर वास्तव में उन मामलों की कम संख्या पर आधारित है, जिनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है। अभी भी बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। ऐसे में ED द्वारा मामलों को निपटाने की दक्षता पर सवाल उठते हैं।
- ▶ ED तथा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के बीच कई बार टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दरअसल कई बार ED, PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए, किसी ऐसी कंपनी की संपत्तियों को कुर्क करने का प्रयास करता है, जो IBC के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) से गुजर रही होती है।
- ▶ साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन सट्टेबाजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से जुड़े अपराधों से निपटने में ED को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बारे में

- ▶ मुख्यालय: दिल्ली में।
- ▶ स्थापना: 1956 में
- ▶ किसके तहत: केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत।
- ▶ किन कानूनों को लागू करने का दायित्व:
 - ⊕ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA): यह धन शोधन को रोकने वाला आपराधिक कानून है और आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने की शक्ति प्रदान करता है।
 - ⊕ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA): यह विदेशी मुद्रा विनियमन के उल्लंघनों से निपटने वाला एक सिविल कानून है।
 - ⊕ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (FEOA): यह आर्थिक अपराध से जुड़े ऐसे भगोड़ों से निपटने के लिए बनाया गया कानून है, जो भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानूनी प्रक्रिया से बचते हैं।
- ▶ अधिकार: तलाशी और संपत्ति की जब्ती; किसी भी व्यक्ति को समन जारी करना, गिरफ्तार करना और मुकदमा चलाना आदि।

अन्य सुर्खियाँ



तेल और गैस पर IEA की रिपोर्ट

द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने 'द इम्प्लिकेशन्स ऑफ ऑयल एंड गैस फील्ड डिक्लाइन रेट्स' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ तेज़ी से घटती दरें: विशेष रूप से शेल और गहरे समुद्र से प्राप्त होने वाले विश्व के तेल और गैस के भंडार तेज़ी से खत्म हो रहे हैं। इससे आपूर्ति कम होने और मूल्य बढ़ने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
- ▶ भारत के लिए चुनौतियाँ: भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चे तेल और 45% प्राकृतिक गैस आयात करता है। ऐसे में इनकी आपूर्ति कम होने पर देश में तेल और गैस संकट उत्पन्न हो सकता है।
- ▶ भारत के लिए नीतिगत सुझाव:
 - ⊕ भारत को कई स्रोतों से आयात करना चाहिए,
 - ⊕ देश में तेल के सामरिक भंडार (स्ट्रेटेजिक रिजर्व) को बढ़ाना चाहिए,
 - ⊕ देश में ही तेल और गैस की खोज में तेज़ी लानी चाहिए, तथा
 - ⊕ ग्रीन हाइड्रोजन तथा जैव-ईंधन जैसे स्वच्छ ऊर्जा विकल्पों को अपनाने को बढ़ावा देना चाहिए।



मोरन समुदाय

मोरन समुदाय ने अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने की मांग को लेकर असम के तिनसुकिया ज़िले में आर्थिक नाकाबंदी शुरू कर दी है।

मोरन समुदाय के बारे में

- ▶ उत्पत्ति और इतिहास: यह असम की देशज जनजाति है, जिसे इस क्षेत्र के सबसे पुराने आदिवासी समूहों में से एक माना जाता है।
- ⊕ यह समुदाय 18वीं शताब्दी में अहोम साम्राज्य के खिलाफ मोआमोरिया विद्रोह (Moamoria Rebellion) का नेतृत्व करने के लिए भी जाना जाता है।
- ▶ सांस्कृतिक पहचान: मोरन समुदाय के लोग पहले अपनी खुद की भाषा बोलते थे, जो दिमासा भाषा से मिलती-जुलती थी, लेकिन वर्तमान में, वे मुख्य रूप से असमिया भाषा बोलते हैं।
- ▶ प्राप्ति क्षेत्र: इस समुदाय के लोग ऊपरी असम, विशेष रूप से तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ और शिवसागर ज़िलों में रहते हैं।



रबी की फसलें

केंद्र सरकार ने 2025-26 के रबी की फसल के लिए खाद्यान्न उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य 362.50 मिलियन टन निर्धारित किया है।

रबी की फसलों के बारे में

- ये फसलें मानसून के लौटने के बाद सर्दियों में (अक्टूबर-दिसंबर) बोई जाती हैं और वसंत ऋतु में (मार्च-अप्रैल) काटी जाती हैं।
- अनुकूल दशाएं: इन फसलों को अंकुरण के लिए निम्न तापमान और कटाई के समय गर्म तथा शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है।
- भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के तहत आने वाली रबी की प्रमुख फसलों में गेहूँ, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, तथा कुसुम शामिल हैं।
 - रबी की अन्य फसलों में मक्का, छोले, तथा जीरा, धनिया, मेथी जैसी वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।



कूनों राष्ट्रीय उद्यान (KNP)

कूनों राष्ट्रीय उद्यान में एक तेंदुए के साथ संघर्ष में एक चीते की मौत हो गई। 2022 में नामीबिया से चीतों को लाए जाने के बाद इस तरह की यह पहली घटना है।

कूनों राष्ट्रीय उद्यान (KNP) के बारे में

- नामकरण: इस उद्यान का नाम कूनों नदी के नाम पर रखा गया है, जो चंबल की सहायक नदी है। चंबल, यमुना की सहायक नदी है।
- अवस्थिति: यह मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है।
- दर्जा: इसे पहले वन्यजीव अभयारण्य और बाद में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
- महत्त्व: यह एशियाई शेरों और चीतों को फिर से बसाने की परियोजना के लिए प्रसिद्ध है।
- वनस्पतियां: यहां मुख्य रूप से करधई, सलाई, खैर जैसे वृक्ष पाए जाते हैं।
- जीव-जंतु: यहां भारतीय तेंदुआ, सांभर, बार्किंग डियर, चौसिंगा, नीलगाय, काला हिरण जैसे जानवर पाए जाते हैं।



SPIN90 प्रोटीन

वैज्ञानिकों ने कोशिकाओं (Cells) की आकार बदलने की क्षमता में SPIN90 प्रोटीन की अहम भूमिका की खोज की है।

- कोशिकाएँ अपने आंतरिक ढांचे (साइटोस्केलेटिन) को अनुकूलित करके उभार (protrusions) बनाती हैं। ये संरचनाएँ रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं, और घाव भरने, रोग-प्रतिरोधक प्रतिक्रिया तथा कैंसर के बढ़ने जैसी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
 - किसी कोशिका का आकार उसकी झिल्ली (Membrane) के पास मौजूद घने और शाखाओं वाले एक्टिन नेटवर्क से निर्धारित होता है। जब कोशिका को कोई उभार बनाना होता है, तो उसे एक्टिन का नया जाल (meshwork) तैयार करना पड़ता है जो इच्छित दिशा में धक्का दे।
 - इस नए एक्टिन जाल का निर्माण SPIN90 प्रोटीन द्वारा नियंत्रित होता है।



अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

भारत सरकार ने व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ वर्गीकरण (International Reference Classification of Occupations: ISCO) को बढ़ावा देने के लिए ILO के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ISCO एक सांख्यिकीय प्रणाली है, जो कार्यों और दायित्वों के आधार पर नौकरियों को सुपरिभाषित समूहों में वर्गीकृत करती है।
 - यह अनुसंधान के साथ-साथ विशेष निर्णय लेने के लिए भी उपयोगी है।

ILO के बारे में

- स्थापना: इसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हस्ताक्षरित वर्साय की संधि के तहत 1919 में स्थापित किया गया।
- सिद्धांत: इसका सिद्धांत है, 'स्थायी और सार्वभौमिक शांति स्थापना के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है।'
- मुख्यालय: जिनेवा (स्विट्जरलैंड)।
- नोबेल शांति पुरस्कार: ILO को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- उद्देश्य:
 - संवाद के माध्यम से सरकारों, नियोजकों और श्रमिकों के बीच सहयोग को मज़बूत करना।
 - कार्यस्थल पर अधिकारों के लिए मानक निर्धारित और करना और उन्हें बढ़ावा देना; महिलाओं और पुरुषों, दोनों के लिए अवसरों को बढ़ाना; और सभी को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना।



छठ महापर्व

केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने छठ महापर्व को यूनेस्को की "मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची" में शामिल करने के लिए कई देशों से नामांकन कराने पर वार्ता की है।

- वर्तमान में भारत के 15 अमूर्त धरोहर यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। इनमें योग, गरबा, दुर्गा पूजा, छऊ नृत्य आदि शामिल हैं।

छठ महापर्व के बारे में

- समर्पित: सूर्य देव और छठी मइया की उपासना की जाती है।
- आयोजन स्थल: मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में।
 - मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड में रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय भी यह पर्व मनाते हैं।
- पर्व का महत्व: यह पर्व प्रकृति के प्रति श्रद्धा, संधारणीयता, समावेशिता और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देता है।



स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025

प्रधान मंत्री ने आनंदकुमार वेलकुमार को स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने और स्केटिंग में भारत के पहले विश्व चैंपियन बनने पर बधाई दी।

- स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 चीन के बेइजिंग में आयोजित हुई।
- एक अन्य भारतीय स्केटर, क्रिश शर्मा ने जूनियर श्रेणी में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता।

सुर्खियों में रहे स्थल



डेनमार्क (राजधानी: कोपेनहेगन)

भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्टैटैजिक पार्टनरशिप के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस साझेदारी का उद्देश्य आर्थिक संबंधों और हरित विकास (Green Growth) को बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लागू करने में योगदान देना है।

भौगोलिक अवस्थिति

- डेनमार्क उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक और स्कैंडिनेवियाई देश है। यह जटलैंड प्रायद्वीप का हिस्सा है और यूरोपीय संघ का सदस्य है।
- स्थलीय सीमा: जर्मनी से लगती है।
- सीमावर्ती जल निकाय: पश्चिम में उत्तरी सागर और पूर्व में बाल्टिक सागर अवस्थित हैं।
- डेनमार्क द्वारा शासित दो विदेशी क्षेत्र हैं – ग्रीनलैंड (दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप) और फ़ैरो द्वीप समूह।

भौगोलिक विशेषताएं

- द्वीप समूह: डेनमार्क लगभग 400 द्वीपों से मिलकर बना द्वीप-समूह है। इनमें सबसे बड़ा द्वीप ज़ीलैंड (Zealand) है।
- सबसे लंबी नदी: गुडेना (Gudena)।
- जलवायु: उत्तर अटलांटिक की गर्म जल धारा (गल्फ स्ट्रीम) यहाँ की जलवायु को संतुलित बनाए रखती है। यहाँ पूरे साल बारिश होती रहती है।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर